सं. 1(11)/2018-समन्वय
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
दिसम्बर, 2024 माह हेतु डीपीई की मासिक उपलब्धियां
*****

1. सीपीएसई और अन्य सरकारी संगठनों में पूंजीगत व्यय:

चुनिंदा सीपीएसई (जिनका वार्षिक कैपेक्स अनुमान 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है) और अन्य सरकारी संगठनों (अर्थात रेलवे बोर्ड, एनएचएआई, डीएमआरसी और डीवीसी) की नवंबर, 2024 की कैपेक्स उपलब्धि की जानकारी दिनांक 5 दिसंबर, 2024 को प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की गई थी। दिनांक 30.11.2024 तक, इन संस्थाओं ने लगभग 4.41 लाख करोड़ रुपये का व्यय कर लिया हैं, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 7.76 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय का 56.84% है।

2. सीपीएसई का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन:

लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के उपलब्ध होने के बाद, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले 91 सीपीएसई के लिए निष्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

3. सीपीएसई का संचालन:

i) भारतीय रेलवे वित्त निगम को नवरत्न का दर्जा देने के रेल मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए दिनांक 18 दिसंबर, 2024 को अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की बैठक आयोजित हुई।

ii) डीपीई ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी:
   (क) दिनांक 11 दिसंबर, 2024 को राइट्स लिमिटेड में तत्काल आमेलन के नियम से गैर-कार्यकारी संवर्ग में 12 पदों की छूट के लिए रेल मंत्रालय का प्रस्ताव।
   (ख) दिनांक 13 दिसंबर, 2024 को आरवीएनएल में तत्काल आमेलन के नियम से बोर्ड स्तर से नीचे के 200 नीचे के पदों की छूट के लिए रेल मंत्रालय का प्रस्ताव।
   (ग) दिनांक 30 दिसंबर, 2024 को आईआरएफसी में तत्काल आमेलन के नियम से बोर्ड स्तर से नीचे के 9 पदों की छूट के लिए रेल मंत्रालय का प्रस्ताव।

(iii) डीपीई ने निम्नलिखित पर अपनी टिप्पणियां भेजी हैं:
   क. दिनांक 4 दिसंबर, 2024 को यंत्र इंडिया लिमिटेड में सीएमडी के पद पर चयन के लिए पात्रता मानदंड में छूट के लिए रक्षा मंत्रालय का प्रस्ताव।
   ख. दिनांक 10 दिसंबर, 2024 को पवन हंस लिमिटेड (पीएचएल) के बेड़े के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी नागर विमानन मंत्रालय का प्रस्ताव।
   ग. दिनांक 12 दिसंबर, 2024 को राजस्थान में ताप और नवीकरणीय बिजली परियोजनाओं के विकास के लिए आरवीयूएनएल के साथ संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर करने संबंधी एनएलसीआईएल द्वारा वांछित स्पष्टीकरण के प्रस्ताव के लिए कोयला मंत्रालय को।
   घ. दिनांक 30 दिसंबर, 2024 को ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), नामरूप, असम के मौजूदा परिसर के भीतर एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप IV उर्वरक संयंत्र की स्थापना के संबंध में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के लिए मसौदा नोट।

4. मंत्रिमंडल सचिवालय अथवा प्रधान मंत्री कार्यालय में लंबे समय से लंबित प्रस्ताव/संदर्भ :-

दिनांक 04.02.2021 की नई पीएसई नीति के अनुसरण में, वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 7 सीपीएसई (ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीआईसी) और नेशनल टेक्सटाइल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीसी) के साथ इसकी 5 सहायक कंपनियों) तथा वाणिज्य विभाग (डीओसी) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 2 सीपीएसई (स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन

ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी) और पीईसी लिमिटेड) को बंद करने के संबंध में सीसीईए नोट के मसौदे की एक अग्रिम प्रति दिनांक 23.08.2022 को प्रधानमंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजी गई थी। इसके अलावा, जब कभी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा पूछा गया, सूचना/स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत किए गए। डीपीई ने हाल ही में दिनांक 09.09.2024 और 04.11.2024 की अंतर्विभागीय टिप्पणी के माध्यम से क्रमशः वस्त्र मंत्रालय और वाणिज्य विभाग के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की। तब से यह मामला प्रधानमंत्री कार्यालय में लंबित है।

5. स्वतंत्र निदेशकों (आईडी) के लिए पदभार और रिक्ति की स्थिति: -

विभिन्न सीपीएसई के बोर्डों में स्वतंत्र (गैर-सरकारी) निदेशकों के 747 पद हैं, जिनमें से दिनांक 31 दिसंबर, 2024 तक 648 पद खाली हैं। 64 सूचीबद्ध सीपीएसई के उद्यमों के निदेशक मण्डलों में आईडी/एनओडी के 200 पद रिक्त हैं तथा ऐसे निदेशक मण्डल सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू सेबी (एलओडीआर) विनियमों के उपबंधों का अनुपालन नहीं करते हैं। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग तथा सीपीएसई आईडी/एनओडी के रिक्त पदों को भरने के लिए लोक उद्यम विभाग को नियमित रूप से स्मरण कराते रहते हैं।

6. अंतर-मंत्रालयी बैठकें और सीसीईए/मंत्रिमंडल नोट:

i. माह के दौरान डीपीई द्वारा 5 आईएमजी/सीएमसीडीसी बैठकों में भाग लिया गया।

ii. लोक उद्यम विभाग ने निम्नलिखित मंत्रिमंडलीय/ईएफसी नोटों पर टिप्पणियां प्रस्तुत कीं।

क. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 15वें वित्तीय चक्र (यानी, वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26) के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब के तहत बजट परिव्यय को 438 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 759.52 करोड़ रुपये करने के लिए व्यय वित्त समिति (ईएफसी) का मसौदा नोट परिचालित किया गया।

ख. घरेलू एलपीजी में अल्प वसूलियों के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को मुआवजे के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा परिचालित ईएफसी नोट।

7. क्षमता निर्माण:

सीपीएसई के 81 कर्मचारियों (वाईपी/वाईएएस सहित) ने दिनांक 31 दिसंबर, 2024 तक आई-गॉट पोर्टल पर 2152 पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं।

8. मिशन भर्ती:

दिसंबर, 2024 में आयोजित रोजगार मेले में सीपीएसई की 1449 नए नियुक्त कर्मियों को शामिल किया गया। अब तक आयोजित रोजगार मेले की 14 श्रृंखलाओं में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा नियुक्त 56979 नए कर्मियों को शामिल किया गया।

9. राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) के लिए सीईओ की नियुक्ति:

एससीएससी के माध्यम से एनएलएमसी के सीईओ को नियुक्त करने का पिछला प्रयास सफल नहीं रहा था। वर्तमान में संयुक्त सचिव, डीपीई एनएलएमसी के अतिरिक्त प्रभार में हैं।

10. लोक उद्यम सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24:

लोक उद्यम सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 - वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के कार्य-निष्पादन पर वार्षिक रिपोर्ट दिसंबर 2024 में संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की गई।

*****